

परंपरागत उद्योगों वाले राज्य की छवि तोड़ने की पूरी तैयारी

सदी की सिल्वर जुबली
2025

10,000

से अधिक युवाओं को मिलेगा रोजगार प्रदेश में डेटा सेंटरों के जरिए



₹25,000

करोड़ का निवेश होगा डिफेंस कॉरिडोर में, 40 हजार युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा



154 एमओयू हो चुके हैं डिफेंस कॉरिडोर के लिए, इनमें 129 इंडस्ट्रियल और 25 इस्टिडयूशनल हैं



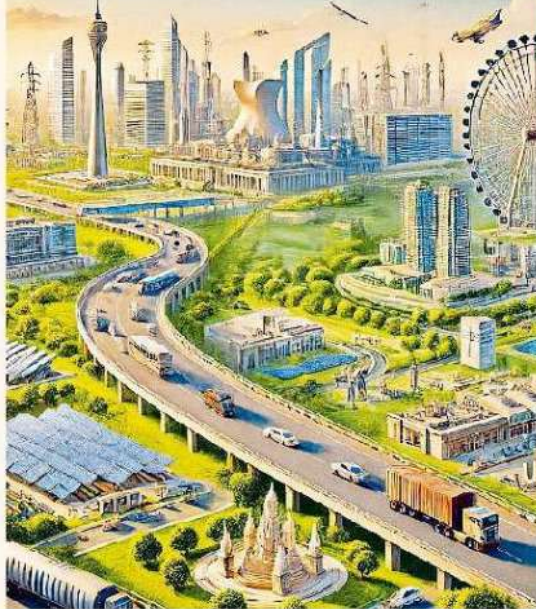
क्या हैं चुनौतियां

- सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर और AI सेक्टर की कंपनियों को आकर्षित करने के साथ यूपी के सामने एक बड़ी चुनौती है कि इन कंपनियों को बेहतर इको सिस्टम मिल सके।
- लैंड लॉक स्टेट होने के नाते यूपी के सामने यह चुनौती भी रहती है कि यहां उत्पादन करने वाली कंपनियां किस तरह अपने प्रॉडक्ट्स को बाहर लेकर जाएंगी। विशेषज्ञों के मुताबिक इसके लिए राज्य सरकार को निर्यातकों के लिए बेहतर इंसेंटिव की व्यवस्था करनी होगी, ताकि उनकी परिवहन की लागत कम हो सके।
- प्रदेश के इंडस्ट्रियल एरिया में आने वाली समस्याओं जैसे-भूमि आवंटन, डबल टैक्सेशन, सिक्वॉरिटी आदि को दूर करना होगा।

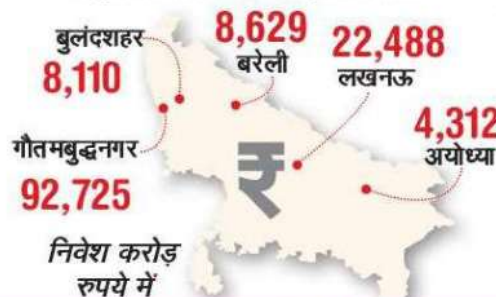
न्यू एज इंडस्ट्री का हब बनेगा UP, बढ़ेंगे रोजगार

एनबीटी ब्यूरो, लखनऊ : देश की सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश को एक समय सिर्फ परंपरागत उद्योगों के लिए जाना जाता था। लेकिन अब प्रदेश की पहचान न्यू एज इंडस्ट्री और एक्सप्रेस-वे जैसे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो रही है। आज यूपी डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर जैसे न्यू एज सेक्टर की कंपनियों के लिए पहली पसंद बनता जा रहा है। इसमें से ज्यादातर कंपनियां ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस-वे अर्थॉरिटी में प्लांट लगा रही हैं। वहीं, यूपी में बनने वाले इंडस्ट्रियल डिफेंस कॉरिडोर में देश-दुनिया की कई बड़ी कंपनियों ने निवेश के लिए प्रस्ताव दिए हैं। इससे जहां नए साल में यूपी इंडस्ट्री का नया हब बनकर सामने आएगा, वहीं हजारों युवाओं को रोजगार भी मिलेगा।

AI Image



यहां सबसे ज्यादा निवेश



FDI पॉलिसी बढ़ाएगी निवेश

प्रदेश में विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार पहली बार FDI पॉलिसी लाई है। पॉलिसी के जरिए निवेशकों को कई तरह की रियायतें दी जा रही हैं। नीति के आने के बाद देश-दुनिया का कई बड़ी कंपनियों ने यूपी आने में रुचि दिखाई है।

डेटा सेंटर-सेमी कंडक्टर हब बनेगी यूपी

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और IT क्रांति के इस युग में देश का डेटा देश में सुरक्षित रहे, यह किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इस चुनौती से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने देश में ही डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की।

ग्रेटर नोएडा में डेटा सेंटर बनाने के लिए एनआईडीपी डिवेलपर्स करीब ₹30 हजार करोड़ का निवेश कर रही हैं। इसके अलावा अदाणी, एसटीटी ग्लोबल, सिफ्री इन्फानाइट, वीएलएस डिवेलपर्स, हीरानंदानी ग्रुप भी ₹90

हजार करोड़ का निवेश कर रही हैं। इससे तीन से पांच वर्ष में रोजगार मिलेगा। वहीं, यमुना एक्सप्रेस-वे अर्थॉरिटी क्षेत्र में वामा सुंदरी इन्वेस्टमेंट के सेमी कंडक्टर इकाई की स्थापना के प्रस्ताव को प्रदेश सरकार ने स्वीकृति दे दी है। कंपनी फॉक्सकॉन के साथ मिलकर ₹3,706 करोड़ का निवेश करेगी। इसमें 3,780 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में ही कैपेस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड ₹4,248 करोड़ का निवेश करेगी।

छोटे हथियारों से मिसाइल तक बनेंगी

डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर यूनिट्स के साथ प्रदेश का बुंदेलखंड इलाका डिफेंस सेक्टर की कंपनियों के लिए पसंदीदा डेस्टिनेशन बनकर उभरा है। इंडस्ट्रियल डिफेंस कॉरिडोर के कानपुर नोड में राज्य सरकार को ₹12,800 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इस नोड में छोटे हथियारों के साथ लाइट बिजनेस जेट और सैटलाइट का भी निर्माण होगा। वहीं, झांसी नोड में ₹8,100 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की तैयारी है। इस नोड में मिसाइल, रक्षा उपकरण, एयरक्राफ्ट अरेस्टर बैरियर नेट्स और सुरक्षा टावरों का निर्माण होगा।

इसके अलावा कॉरिडोर के लखनऊ, अलीगढ़, आगरा और चित्रकूट नोड में भी निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। लखनऊ नोड में ब्रिक्स मिसाइल का निर्माण किया जाएगा।